भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3321
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व

3321. श्री मुरारी लाल मीना :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों, क्षेत्रों और महिलाओं के अपेक्षाकृत असमान प्रतिनिधित्व की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सामाजिक श्रेणी, लिंग और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संबंध में समेकित आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी में वृद्धि करने के संबंध में कोई अध्ययन या परामर्श किया है, यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता, समान अवसर और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। अतः

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार आँकड़े केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर समुचित विचार किया जाए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केवल उन्हीं व्यक्तियों की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है, जिनकी संस्तुति उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा की जाती है।

****